

संख्या : १८२ / श०वि० / आ०-०४-१३(वजर) / २००३

प्रेषक,

ठी०के० गुप्ता,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
अद्वकुम्भ मेला-2004
हरिद्वार, उत्तरांचल।

आवास एवं शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक ३ मार्च, 2004

विषय : वित्तीय वर्ष 2003-04 अद्वकुम्भ मेला-2004 हरिद्वार की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उत्तरांचल पैयजल निगम के अन्तर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं० 1664/एस०टी०/मेला/बजट, दिनांक 20फरवरी, 2004, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ताहसील प्रांगण ज्वालापुर में उच्च जलाशय निर्माण एवं नलकूप निर्माण से रामबन्धित शासनादेश संख्या-371 / श०वि०-आ०-2002-13(बजट) / 2002टी०री०, दिनांक 10फरवरी 2003 जिसके द्वारा उक्त कार्य हेतु रु० 84.90लाख की लागत के आगणन के विपरीत अवगुक्त धनराशि रु० 34.90 लाख की धनराशि स्वीकृति की गई थी, के कम में गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्य हेतु अवशेष धनराशि कमशः रु० 50.00लाख (रु० 50.00लाख मात्र) की धनराशि को व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1) उक्त धनराशि का व्यय शहरी विकास / आवास अनुभाग के शासनादेश संख्या-622 / श०वि०-आ०-2004 -51(एच०के०एम०) / 2003, दिनांक: 12 फरवरी, 2004 द्वारा बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि से ही वहन किया जायेगा।
- (2) उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर रामबन्धित कार्यदायी संरथाओं को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी और इस धनराशि का दिनांक 31-03-2004 तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- (3) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिये किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना / मद में नहीं किया जा सकेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व रामी योजनाओं / कार्यों पर सम्बन्धित मानवित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीक दृष्टिकोण से समर्त

- औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टयों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- (5) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर रवीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
- (6) स्वीकृत कार्य करते समय वित्तीय हरतपुरितका, बजट गैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपाल सुनिश्चित किया जाये। एक मुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये और इन पर यदि किस तकनीक अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
- (7) सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अप्रेत्तार धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
- (8) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रताव अधिलम्ब भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।
- (9) कार्य कराने से पूर्व रथल का भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा अवश्य करा लिया जाये एवं निरीक्षण के पश्चात रथल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाये।
- (10) निर्माण कार्य पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये, तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31-3-2004 तक पूर्ण उपयोग एवं उक्त कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को एवं उपयोगिता प्रगाण पत्र भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- (12) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु राम्बन्धित विभाग/निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। कार्य की समयबद्धता हेतु मेलाधिकारी राम्बन्धित निर्माण एजेन्सी से अनुबन्ध कर उन पर पैनाल्टी व्लाज लगाने पर भी विचार कर सकते हैं।
- (13) आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण विभाग द्वारा मुख्य अभियंता द्वारा रवीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (14) उपकरणों/सामग्रियों आदि का डी०जी०एस० एण्ड डी० की दरों पर अथवा टेप्लर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
- (15) वित्त विभाग के शासनादेश स०-०३-वित्त विभाग/टी०ए०री०-अनुभाग देहसादून दिनांक 23-10-2003 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

2. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003-04 के आय-व्यय के अनुदान सं0-13-लेखा शीर्षक 2217-शहरी विकास-80-सामान्य-आयोजनागत-800-अन्य-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-01-हरिद्वार कुम्भ मेला हेतु अवस्थापना सुविधा-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० सं० ३५८९ वि० अनु० ३/२००३ दि० ३१ मार्च, २००४ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी०के० गुप्ता)

अपर सचिव,

संख्या : १५८९

(१) / श० वि० / आ०-०४ तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), लेखा परीक्षा उत्तरांचल, देहरादून।
 2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कैम्प कार्यालय, देहरादून।
 3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
 4. अधिशासी अभियन्ता, पैदल निगम, हरिद्वार।
 5. श्री एल०एम० पन्ता, वित्त, बजट अनुभाग।
 6. नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त अनुभाग-३, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
 7. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तरांचल सचिवालय।
 7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
 8. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
 9. गार्ड बुक।

आज्ञा रो.

१५८९

(डी०के० गुप्ता)

अपर सचिव,